

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फ़ैक्स नं० (0135) 2713724 फ़ोन नं० (0135) - 2713551

संख्या 264 /XXV-12 (P-14)/2021 देहरादून: दिनांक 23 फरवरी, 2026

सेवा में,

पंजीकृत

श्री सुरेन्द्र सिंह थापा,
174-पंडितवाडी-प्रेमनगर
जिला देहरादून। पिन-248001
मो0-9897866488

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बावत।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 12.02.2026 इस कार्यालय में दिनांक 16.02.2026 को प्राप्त हुआ है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 से 4 तक की सूचना की मांग की गई है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत करना है कि आपके वर्णित पत्र से सम्बन्धित सूचनायें आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या-99 दिनांक 22.01.2026 के द्वारा पूर्व ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान समय में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु जनपद स्तर पर एक-एक लोक सूचना अधिकारी तैनात/कार्यरत हैं। सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालय से नियमानुसार सूचना प्राप्त की जा सकती हैं।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़,
देहरादून-248001
मो0नं0-9897995591

Digitally signed by
BASANT SINGH RAWAT
Date: 20-02-2026

12:12:44
(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0 9411740189

Date 3/2/16

सेवा मे.

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,

सचिवालय परिसर 4 - सुभाष रोड देहरादून - 248001

विषय : व्यपाक देश हित और समाज हित मे एस आई आर प्रकिया मे नागरिकों के संग आ रही समस्या के समाधान हेतु निवेदन

महोदय,

जैसा कि आपके संज्ञान मे हैं कि, हमारे द्वारा विकास नगर ग्राम बाढ़वाला देहरादून के नागरिकों के अनुरोध पर एस आई आर की जानकारी देने हेतु दिनांक :10/1/26. को एक कार्यशाला की गई थी, जहाँ कुछ पीड़ित नागरिकों द्वारा कुछ सवाल किये गये /समस्याओ से हमें अवगत कराया गया और समाधान माँगा, क्योंकि हम एस आई आर प्रकिया से भली भाँति परिचित नहीं थे, इसलिए उनके सवालों का उस वक्त कोई भी जवाब देना हमें उचित नहीं लगा, पीड़ित नागरिकों के द्वारा जो समस्या बताई गई जो निम्नलिखित हैं

- (1) हमें यहाँ रहते हुए 15, 20 साल हो गये मगर संबंधित अधिकारी हमसे 1987 का रिकॉर्ड मांगते हैं, अब हम 1987 का रिकॉर्ड कहा से लाये ?
- (2) बुजुर्गों द्वारा गरीबी के कारण कोई जमीन जायदाद नहीं खरीद सके हम लोग का जीवन किरायेदारी मे ही गुजर रहा हैं, संबंधित अधिकारी जमीन के कागज मांगते हैं, ऐसे मे हम कहा से जमीन जायदाद कागज जात लेकर आए.?

कुछ नेपाली नागरिक भी थे जिनकी द्वारा निम्नलिखित हैं समस्या बताई गई -

- (1) हम लोग नेपाल से भारतीय सेना मे भर्ती हुए थे, भारत देश की सेवा के उपरांत हमारे बच्चे यही पैदा हुए यही उच्च शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और हम रिटायरमेंट के बाद भारत मे ही बस गये, मगर हमारे बच्चों के आवेदनो को इसलिए निरस्त कर दिया जा रहा कि, आपके पिता के आर्मी रिकॉर्ड मे नेपाल का पता लिखा हैं ऐसे मे हमारे बच्चे और हम कैसे एस आई प्रकिया पूरा कर सकेंगे?
- (2) कुछ महिलाओ का कहना था कि हमारा मायका नेपाल हैं और हमारा विवाह एक भारतीय पुरुष से हुआ हैं और अब भारत मे बस गई हैं, ऐसे मे क्या हम नेपाल की बेटी जो अब भारत मे बहु बनकर आई हैं एक नेपाली माता पिता का रिकॉर्ड जमा कर एस आई आर मे वोटर बन सकते हैं?

महोदय आपसे निवेदन हैं कि -व्यपाक देश हित और समाज हित मे एस आई आर प्रकिया मे उपरोक्त नागरिकों के संग आ रही समस्याओ का संज्ञान लेते हुए बिंदवार समस्याओ का निम्नलिखित समाधान करने का कस्ट करे

- (1) क्या जो व्यक्ति /परिवार उत्तराखंड मे 1987 के बाद से 15, 20 से साल निवास कर रहा हैं उसे भी 1987 का रिकॉर्ड दिखाना जरूरी हैं
- (2) जो व्यक्ति/परिवार वर्षों से निवास कर रहे मगर उनके नाम पर कोई जमीन ज्यादाद नहीं हैं तो क्या ऐसे व्यक्ति/परिवार एस आई आर प्रकिया से बाहर हो जायेंगे
- (3) नेपाल से भर्ती फौजी जो यही बस गये जिनके पिता के पते पर नेपाल का पता अंकित हैं उनके बच्चों के लिये क्या प्रावधान हैं,

- (4) नेपाली बेटी जो भारत के पुरुषो संग विवाह कर भारत मे बस गई उनके लिए क्या प्रावधान हैं
- (5) भारत- नेपाल 1950 सन्धि अनुसार नेपाल से विस्थापित हुए परिवारों ने यह भी अवगत कराया था कि हमें यहाँ रहते हुए 30,40 वर्ष हो गये हैं अब हमारा नेपाल से कोई संबंध नहीं रहा मगर फिर भी हमारा वोटर आई डी इसलिए नहीं बनाते की हम नेपाल के है हमारे पास कोई भी जमीन के कागज भी नहीं हैं किराये के मकानों मे ही निवास करते आ रहे हैं

ऐसे व्यक्तियों के लिए एस आई आर क्या प्रावधान हैं

यह भी संज्ञान लाना हैं कि आर टी आई से प्राप्त जानकारी मे संगलग्न - "Enumeration Form" के DELARATION के एक बिंदु मे उल्लेख किया गया हैं कि -. "If any parent is not Indian, provide a copy of his/her valid passport & visa at the time of your birth"

महोदय संज्ञान मे लाना हैं कि भारत- नेपाल के बीच 1950 की सन्धि अनुसार वीजा पास पोर्ट का कोई प्रावधान ही नहीं हैं, और दोनों देशो मे किसी के भी नागरिक को अवैध निवासी नहीं माना जाता देखे Annexure C 24,25

अतः महोदय से निवेदन हैं कि - व्यापक देश हित और समाज हित मे हमारे द्वारा नागरिको की जो समस्याए आपके समक्ष बिंदुवार रखी गयी हैं उन उपरोक्त बिंदुवार समस्याओ का अविलम्ब समाधान करते हुए एस आई आर प्रक्रिया को नागरिकों के हित मे सरल बनाते हुए हमें अवगत काराने का कस्ट करे,

"अवैध घुस ना पाए, वैध छूट ना पाए"

तभी एस आई आर प्रक्रिया मकसद पूरा होगा

धन्यवाद

भवदीय



सुरेंद्र सिंह थापा

संगठन सचिव आर टी आई क्लब उत्तराखंड -

174 पंडितवाड़ी, शाहपुर, शहीद कपिल थापा मार्ग,

नजदीक काली मंदिर, प्रेमनगर देहरादून उत्तराखंड- 248007,

9897866488

मैं आपका सचिव
आर टी आई क्लब
संगठन सचिव
आर टी आई क्लब